

कॉलेज-यूनिवर्सिटी के दस लाख विद्यार्थियों का सिलेबस एक होगा

हर्ष खटाना | जयपुर

प्रदेश के कॉलेज- विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10 लाख विद्यार्थियों का अब एक समान कोर्स व सिलेबस होगा। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा और स्तर एक समान हो सकेगी। इस दिशा में राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने हायर एजुकेशन के एसीएस राजहंस उपाध्याय को इसे एक्जामिन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसे कैसे लागू कराया जाएगा? डिपार्टमेंट के लोग इसका खाका तैयार करने में लग गए हैं। प्रदेश के समस्त जिले 11 से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में बंटे हुए हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों का यूजी-पीजी का सिलेबस कुछ हद तक भिन्न है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स तक के सिलेबस अलग-अलग हैं। ऐसे में लंबे समय से कोर्स व सिलेबस में एकरूपता की बात की जा रही थी।



यूं समझे, कोर्स-सिलेबस अलग-अलग कैसे?

प्रत्येक विश्वविद्यालय में विषयवार बोर्ड ऑफ स्टडीज की एक कमेटी है। ये कमेटी ही कोर्स और सिलेबस का निर्धारण करती है। कुछ विश्वविद्यालयों में कोर्स व सिलेबस 10-10 साल तक अपडेट नहीं होने के मामले उठ चुके हैं। मामले में राज्यपाल कल्याण सिंह कई बार वीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में कुलपतियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष आपत्ति जता चुके हैं।

स्टैंडर्ड एजुकेशन के फायदे

- एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार होगा और देश-विदेश में राजस्थान की डिग्रियों की साख बढ़ेगी।
 - हिस्ट्री में कई बातों को लेकर इतिहासकारों और शिक्षाविदों में मतभेद है, मतभेद और विवादित बातें पढ़ाई जा रही हैं। स्टैंडर्ड एजुकेशन में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में साइंस विषय में डिसेक्शन यानी जीव-जंतुओं की चीर-फाड़ कहीं लागू है और कहीं बेन है। जहां बेन है, वहां स्लाइड से पढ़ाया जा रहा है। इसका भी समाधान होगा कि डिसेक्शन रहेगा या हटेगा।
 - शिक्षा की दृष्टि से प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बड़ा-छोटा नहीं रह जाएगा। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की नजर में प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पासआउट विद्यार्थी समान ही होगा।
 - प्रदेशभर के पब्लिशर स्टैंडर्ड प्रोफेसरों की किताबें छाप सकेंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ स्टडीज व पब्लिशरों की मिलीभगत पर भी असर पड़ेगा।
 - हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड एजुकेशन चाहते हैं, इसलिए इस दिशा में काम की शुरुआत है। इन सब बातों के लिए एसीएस को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे हर पहलू को एक्जामिन करा लें, एसीएस की रिपोर्ट के बाद ही बता सकेंगी कि इसे कब तक लागू कराया जाएगा।
- किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री